

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

सिंचाई विभाग

देहरादून : दिनांक 24 सितम्बर, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए आयोजनागत मदों में जिला योजना के अन्तर्गत धनावंटन।

महोदय,

जिला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27.3.008 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2008-09 में जिला योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत रु0 787.69 लाख (रुपये सात करोड़ सतासी लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण संलग्नक-1 में अंकित है, को जनपदों में स्थित सिंचाई खण्डों में आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के लिए किया जाए जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2- जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं पर किया जाए जो जिला अनुश्रवण समितियों से अनुमोदित है।
- 3- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
- 4- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- 5- स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।
- 6- जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
- 7- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.....2

- 8— मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- 9— विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 10— जिलाधिकारियों के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 11— मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी०एम०-17 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 12— जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का आहरण डी०सी०एल० हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की अनुदान सं०-30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीषकों/उपलेखाशीषकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव

3194
संख्या / ११-२००८-०३(४१)/०३, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. वित्त अनुभाग-2
4. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
5. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
8. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
11. गार्ड फाईल ।

संलग्न : यथोक्त

आशा से

(एस०एस०टोलिया)
अनु सचिव